

इस्लामिक सहयोग संगठन और भारत

प्रलिस के लयः

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC), संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परषिद

मेन्स के लयः

भारत के हतऱों पर देशों की नीतयऱों और राजनीतिका प्रभाव, एक संगठन के रूप में OIC के साथ भारत का संबंघ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने कर्नाटक हजिाब वविाद के बीच [इस्लामिक सहयोग संगठन](#) के सांप्रदायिक वचिारों के कारण इसकी आलोचना की है ।

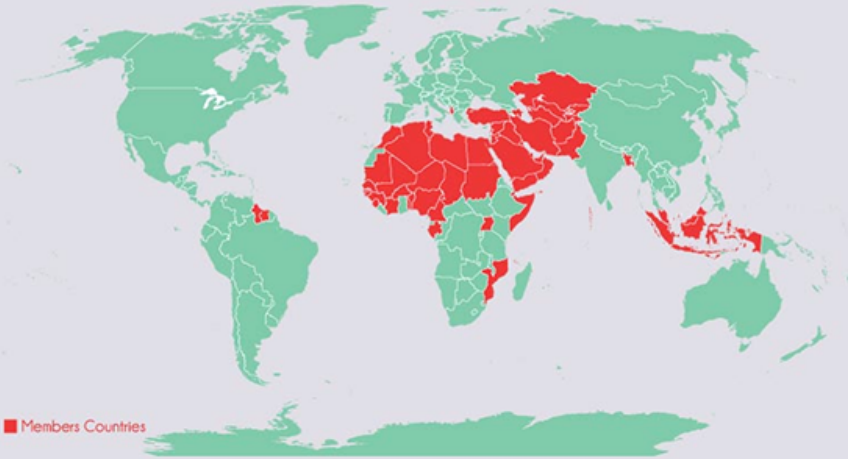
OIC और भारत के बीच हालया वविादः

- **OIC का कथनः** मुस्लिम छात्राओं को कर्नाटक के स्कूलों में हजिाब नहीं पहनने के लयऱे कहे जाने के मुददे पर OIC ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परषिद से "आवश्यक उपाय" अपनाने का आह्वान कया है ।
 - OIC ने भारत से आग्रह कया कविह "मुस्लिम समुदाय की जीवन-शैली के तरीकों की रक्षा करते हुए उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चति करे" ।
- **भारत की प्रतिकरयाः** भारत ने कहा कविह एक लोकतांत्रिक देश है और देश के भीतर मुददों को संवैधानिक ढाँचे और तंत्र के साथ-साथ लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीतिका अनुसार हल कया जाता है ।

इस्लामिक सहयोग संगठनः

- **परचियः**
 - कुल 57 देशों की सदस्यता के साथ यह संयुक्त राष्ट्र (UN) के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है ।
 - यह संगठन दुनया भर में मुस्लिम जगत की सामूहकता का प्रतिनिधित्व करता है ।
 - यह दुनया के वभिन्न देशों के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही दुनया के मुस्लिम समुदायों के हतऱों की रक्षा एवं संरक्षण का प्रयास करता है ।
 - इसका गठन सतंबर 1969 में मोरक्को के रबात में हुए ऐतहासिक शखिर सम्मेलन के दौरान कया गया था, जसिका लक्ष्य वर्ष 1969 में एक 28 वर्षीय ऑस्ट्रेलयाई द्वाारा येरुशलम में अल-अक्सा मसजिद में आगजनी की घटना के बाद इस्लामीक मूल्यों को सुरक्षा प्रदान करना था ।
 - **मुख्यालयः** जेद्दाह (सऊदी अरब)

What is OIC?



OIC- Organization of the Islamic Cooperation

It was founded in **1969**

First OIC Charter Adopted in **1972**



Key Bodies of OIC:

Number of Member Countries

57

Founding Members **30**

- ▶ Council of Foreign Ministers
- ▶ General Secretariat
- ▶ Islamic Summit
- ▶ Al-Quds Committee

//

OIC के साथ भारत के संबंध:

- दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुसलमि समुदाय वाले देश के रूप में भारत को वर्ष 1969 में रबात में संस्थापक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर अपमानजनक तरीके से भारत को बाहर कर दिया गया।
- भारत कई कारणों से अब तक इस संगठन से दूर रहा:
 - भारत एक ऐसे संगठन में शामिल नहीं होना चाहता था जो धर्म के आधार पर गठित किया गया हो।
 - साथ ही जोखिम था कि सदस्य देशों के साथ व्यक्तिगत तौर पर द्विपक्षीय संबंधों में सुधार से वह एक समूह के दबाव में आ जाएगा **खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर।**
- वर्ष 2018 में **वर्द्धित मंत्रियों के शिखर सम्मेलन के 45वें सत्र** में मेज़बान बांग्लादेश ने सुझाव दिया कि भारत, जहाँ दुनिया के 10% से अधिक मुसलमान रहते हैं, को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाना चाहिये, लेकिन पाकिस्तान द्वारा प्रस्ताव का वरिध किया गया।
- संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के बाद भारत समूह के किसी भी बयान पर भरोसा करने के लिये आश्वस्त है।
 - भारत ने लगातार इस बात को रेखांकित किया है कि जम्मू-कश्मीर **"भारत का अभिन्न अंग है और यह भारत का आंतरिक मामला है"** तथा इस मुद्दे पर OIC का कोई अधिकार नहीं है।
- वर्ष 2019 में भारत ने OIC के **वर्द्धित मंत्रियों की बैठक** में **"गेस्ट ऑफ ऑनर"** के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की।
 - इस पहले निर्माण को भारत के लिये एक **कूटनीतिक जीत** के रूप में देखा गया, विशेष रूप से ऐसे समय में जब पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ गया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

